

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवार्थे,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 21 अगस्त, 2007

विषय:-श्री शिवाजी राय गायकवाड़ उर्फ रजनीकान्त (फिल्म अभिनेता) को ग्रामीण संस्कृति के उत्थान (नृत्य कला केन्द्र) की स्थापना हेतु तहसील ऋषिकेश के ग्राम गोहरीमाफी में कुल 0.2310 है0 भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1244/12ए-150 (2005-08)/ डी.एल.आर. सी. दिनांक 18 मई, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्री शिवाजी राय गायकवाड़ उर्फ रजनीकान्त (फिल्म अभिनेता) को ग्रामीण संस्कृति के उत्थान (नृत्य कला केन्द्र) की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क) (IV) के अन्तर्गत तहसील ऋषिकेश के ग्राम गोहरीमाफी में कुल 0.2310 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं-

1- केंता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि करने के लिये अर्ह होगा।

2- केंता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा -129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- केंता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी

.....(2)

अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागे होंगे।

4- जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है वह सीलिंग भूमि न हो।

7- शासन द्वारा दी गयी भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

8- उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- सचिव, संस्कृति, उत्तराखण्ड शासन।

3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

4- श्री शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ रजनीकान्त, 18-राघवावीरा, एवन्यू पॉयस गाडर्न, चैन्नाई(तमीलनाडु)।

5- एन0आइ0सी0, सचिवालय परिसर।

6- गाड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनुसचिव।